## विवरण-2

**उन सुविधाओं/सहायता के ब्यौरे जो केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पाने वालों तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों/आश्रितों को प्रदान की जाती है**

1. स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं/परिचर को आजीवन मुफ्त रेलवे पास (प्रथम श्रेणी/ए०सी०-II टायर) की सुविधा।

2. केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में भी मुफ्त चिकित्सा सुविधा। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को भी सी०जी०एच०एस० सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

3. यदि राष्ट्रीय हित में या अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक समझा जाता है तो स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में आवासीय निवास की सुविधा। स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को आबंटिती व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् केवल छः माह की अवधि के लिए सरकारी आवास रखने की अनुमति दी जाएगी।

4. ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली में स्थापित "फ्रीडम फाइटर होम" में स्थान।

5. स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं को, यदि संभव हो, संस्थापन के बिना और किराए का केवल आधे का भुगतान करने पर टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा।

6. स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्री/पुत्रियों के विवाह के अवसर पर गृह मंत्री के विवेकानुदान से वित्तीय सहायता।

### Central Teams for States

2346. **SHRI N.R. DASARI:**
**SHRI J. CHITHARANJAN:**

**Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:**

(a) whether it is a fact that central teams were sent to Bihar, West Bengal and Tamil Nadu to assess the law and order situation in these States;

(b) if so, the details and findings thereof;

(c) whether the Chief Ministers of these States have objected to this discriminatory action on the part of Government; and

(d) if so, the details and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) The reports of these teams have been received and these relate to prevailing law & order situation in these States and steps taken by them to instil confidence among the people.

(c) and (d) Reservations have been expressed by some political leaders about the constitutionality of sending Central teams to the States.

Article 355 of the Constitution of India casts a duty on the Union to protect every State not only against external aggression but also internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution. In the discharge of this duty, the Central Government is expected to keep itself posted with respect to goings on in all States. Visits of Central officials to the States are part of this process. The Central and State Government have all along been interacting on issues relating to law and order.

### Recovery of Explosives in Tamil Nadu

2347. **SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:**

**(a) whether Government are aware of the increasing number of cases of recovery of chemical weapons, explosives and other such materials in Tamil Nadu;**

(b) if so, what effective steps Government have taken so far, to curb/check such anti-national activities; and

(c) whether any discussions were held between Government and the affected States so as to find out the reasons behind it?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Chemical weapons as such have not been recovered so far. However, there have been instances of recovery of explosives and other materials.

(b) A number of persons have been arrested and cases registered against them. Raids are being organised regularly for recovery of explosive substances. The Al-Ummah and the Jehad Committee have been declared as unlawful organisations by the State Government. Further, the State Government, during the last Assembly Session passed a Bill called the 'Tamil Nadu Prevention of Terrorist Activities Act, 1998' to check the forces of fundamentalism and terrorrism in the State.

(c) Yes, Sir.

**जाली करेंसी मुद्रा रखने वाले पाकिस्तानी नागरिक**

2348. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में जाली करेंसी मुद्रा चलाने में कितने पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) क्या इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई० एस० आई० का हाथ पाया गया है; और

(ग) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षति पुहंचाने के लिए यह पाकिस्तान की एक साजिश है?

**गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी):** (क) से (ग) सरकार को देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद को बढ़ाने तथा तोड़-फोड की गतिविधियों द्वारा भारत को अस्थिर करने की पाकिस्तान की आई०एस०आई० के नापाक इरादों की जानकारी है। पाक आई०एस०आई० नशीली दवाईयां तथा जाली करेंसी मुद्रा की तस्करी करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में काम कर रहे तस्करों को भी संरक्षण प्रदान कर रही है ताकि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके। केन्द्र सरकार, राज्य प्राधिकारियों द्वारा, अपराध-वार व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित कोई सूचना नहीं रखती है।

**उच्चतम न्यायालय को धमकी**

2349. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ संगठन प्रमुखों ने उच्चतम न्यायालय को यह धमकी दी है कि यदि अयोध्या विवादित स्थल के मामले में फैसला उनके विरुद्ध किया गया तो उच्चतम न्यायालय को भी धर्म अदालत में बुलाकर सजा दी जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे संगठनों और उनके प्रमुखों के विरुद्ध क्या कदम उठा रही है?

**गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी):** (क) सरकार को अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

**Shukla Commission Report**

2350. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the measures taken by Government for transforming the North East on the basis of the suggestions of High Level Commission Report submitted to Prime Minister on March 7, 1997; and

(b) the concrets steps proposed by Government as per the S.P. Shukla Commission's Report?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) The High Level Commission (HLC) for the North East headed by Shri S.P. Shukla, the then Member, Planning Commission, submitted its report to the then Prime Minister on March 7, 1997. The HLC critically examined the backlog in Basic Minimum Services (BNS) and